भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2621
19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

फूड पार्क

2621. डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितने फूड पार्कों की स्थापना की गई है;

(ख) झारखंड में स्थापित किए गए नए फूड पार्कों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या सरकार का देश में और अधिक फूड पार्क स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2008 से 2021 तक देश भर के विभिन्न राज्यों में पीएमकेएसवाई की एक उप योजना मेगा फूड पार्क स्कीम (एमएफपी) के तहत खाद्य पार्कों (निजी और सार्वजनिक दोनों) की स्थापना के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना को सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2021 से केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के प्रावधान के साथ बंद कर दिया गया है। वर्ष 2008 से 2021 की अवधि के दौरान**,** पूरे देश में 41 एमएफपी स्थापित किए गए हैं। यह योजना मांग आधारित थी और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर आमंत्रित अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे।

इसी तर्ज पर, वर्तमान में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन योजना (मिनी फूड पार्क) कार्यान्वित कर रहा है, जो कि आधुनिक अवसंरचना के विकास के लिए पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एक घटक स्कीम भी है ताकि उद्यमियों को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अर्थात वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक) के दौरान:

(i) <u>मेगा फूड पार्क योजना के तहत</u>, 4 मेगा फूड पार्क (एमएफपी) परियोजनाएं, जिन्हें वित्त वर्ष 2020-2021 के दौरान पहले से ही सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया था, को इस मंत्रालय द्वारा अंतिम अनुमोदन दिया गया था और 6 एमएफपी परियोजनाएं, जिन्हें पहले मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, प्रचालित हो गई हैं।

(ii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के अंतर्गत 43 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और 15 प्रचालित हो चुकी हैं।

एमएफपी और एपीसी स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

हालांकि, झारखंड राज्य से मेगा फूड पार्क स्कीम अथवा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना के अंतर्गत कोई पात्र प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

अनुबंध

फूड पार्क के संबंध में दिनांक दिनांक 19.12.2023 को लोकसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2621 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मेगा फूड पार्क (एमएफपी)			
क्र.स.	**वित्तीय वर्ष**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**प्रचालित परियोजनाओं की संख्या**
1.	2020-21	0	4
2.	2021-22	2	1
3.	2022-23	2	0
4.	2023-24	0	1
कुल		**4**	**6**
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी)			
क्र.स.	**वित्तीय वर्ष**	**अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या**	**प्रचालित परियोजनाओं की संख्या**
1.	2020-21	18	3
2.	2021-22	2	7
3.	2022-23	17	2
4.	2023-24	6	3
	कुल	**43**	**15**